2010:CGHC:350-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठः माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

द्वितीय अपील क्रमांक 206/2007

अपीलार्थीगण मूर्ति श्री सिंहवाहिनी देवी,
सिंहवाहिनी देवी मंदिर, राजापारा एवं अन्य

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

उपस्थितः

अपीलार्थीगण की ओर से	:	श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता।
राज्य/प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से	:	श्री सुशील दुबे, शासकीय अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से	:	श्री रवींद्र अग्रवाल, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी संख्या 3	:	यद्यपि वाद-शीर्षक में उल्लेखित है किन्तु पहले ही निधन हो चुका है।

व्यव्हार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अधीन द्वितीय अपील

निर्णय

(23 अप्रैल, 2010 को पारित)

व्यव्हार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अधीन यह द्वितीय अपील वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है जिनका घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, हालांकि, अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी संख्या 1, देवता के पक्ष में वाद संपत्ति का स्वामित्व घोषित किया और वादी संख्या 2/अपीलार्थी संख्या 2 के वादी संख्या 1, देवता/मंदिर के सर्वाराकार के रूप में घोषणा के दावे को निरस्त कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. वादी संख्या 1 सिंहवाहिनी देवी की मूर्ति, सिंहवाहिनी मंदिर, राजापारा, कांकेर है और वादी संख्या 2/अपीलार्थी संख्या 2 स्वयं को वादी संख्या 1 का सर्वाराकार होने का दावा करता है।

वाद में निम्नलिखित अनुतोष का दावा किया गया था :-

(i) वादी संख्या 1 को ग्राम बन्सपट्टर में 30.00 एकड़ क्षेत्रफल वाले 10 खसरा नंबरों पर स्थित भूमि तथा नजूल प्लॉट नंबर 15 क्षेत्रफल 211 वर्ग मीटर पर स्थित मंदिर का स्वामी घोषित किया जाए।

(ii) वादी संख्या 2 लक्ष्मीनारायण को वादी संख्या 1, देवता का सर्वाराकार घोषित किया जाए।

(iii) प्रत्यर्थी संख्या 1, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जिला कलेक्टर, कांकेर के माध्यम से सार्वजनिक न्यास के पंजीयन तथा न्यास के प्रबंधक के रूप में कलेक्टर के नाम का अभिलिखित किया जाना अवैध, शून्य और अप्रवर्तनीय घोषित किया जाए।

(iv) राजस्व प्रकरण संख्या 1/बी-113/93-94 दिनांक 16-8-1994 द्वारा पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, कांकेर द्वारा सार्वजनिक न्यास का गठन और पंजीयन अवैध और अप्रभावी घोषित किया जाए।

(v) प्रत्यर्थीगण को वाद भूमि और मंदिर में वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जाए।

3. वाद दिनांक 11-4-1992 को यह तर्क देते हुए प्रस्तुत किया गया कि सिंहवाहिनी की मूर्ति, जो वादी संख्या 1 है, एक न्यायिक व्यक्ति है जिसे कांकेर के राजापारा में स्थित सिंहवाहिनी के मंदिर में स्थापित किया गया था। कहा गया कि उक्त देवता की प्रतिष्ठा और स्थापना कांकेर राज्य के भूतपूर्व शासक श्री कोमलदेव द्वारा अपनी कुल-देवी (पारिवारिक देवी) के रूप में राजापारा में मंदिर का निर्माण करके की गई थी। उनकी मृत्यु के बाद, भूतपूर्व शासक के वैध उत्तराधिकारी राम-नवमी, दशहरा, दीपावली और अन्य विशेष अवसरों पर देवता की पूजा करते रहे और शेष दिनों में मंदिर बंद रहता था और आम जनता को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार, यह भूतपूर्व शासक का यह एक व्यक्तिगत मंदिर था, जिसे 1985 में शाही परिवार के वर्तमान प्रमुख, यथा, महाराजाधिराज श्री उदय प्रताप देव द्वारा जनता के लिए खोल दिया गया था। देवता के पास ग्राम बन्सपट्टर में 30.00 एकड़ भूमि और राजापारा, कांकेर में शीट नंबर 13, प्लॉट नंबर 15 पर 211 वर्ग मीटर का भूखंड है जिस पर मंदिर का निर्माण किया गया है। वादीगण के अनुसार, संपत्ति की देखभाल और प्रबंधन उसके सर्वाराकार सुंदर सिंह, पदम सिंह और पन्नालाल द्वारा किया जाता था, जो वादी संख्या 2 लक्ष्मीनारायण के पूर्वज हैं। पन्नालाल का 1985 में निधन हो गया और उसके बाद वादी संख्या 2 को वादी संख्या 1, देवता के अनुयायियों और भक्तों द्वारा सर्वाराकार नियुक्त किया गया और तब से वादी संख्या 2 सर्वाराकार का कार्य कर रहा है। तहसीलदार, कांकेर ने वर्ष 1974-75 में कृषि भूमि के प्रबंधक के रूप में कलेक्टर, बस्तर का नाम वादी संख्या 1 को सूचित किए बिना अवैध रूप से अभिलिखित कर लिया, जबकि कलेक्टर, बस्तर ने मंदिर के मामलों में कभी कोई रुचि नहीं ली। कलेक्टर, बस्तर को वादी संख्या 1 द्वारा कभी प्रबंधक नियुक्त नहीं किया गया। वादी संख्या 2 ने उसके नाम को सर्वाराकार के रूप में अभिलिखित कराने के लिए अतिरिक्त कलेक्टर, कांकेर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 10-7-1990 को अस्वीकार कर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिया गया और मंदिर को सार्वजनिक न्यास घोषित करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश या सार्वजनिक न्यास का पंजीयन अवैध और शून्य है।

4. वादपत्र में आगे कहा गया था कि सार्वजनिक न्यास के पंजीयन के बाद, प्रत्यर्थी मंदिर के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए, यह वाद प्रस्तुत किया गया है।

5. प्रत्यर्थीगण ने अपना लिखित तर्क प्रस्तुत किया और कहा कि वादी संख्या 2 मंदिर का सर्वाराकार नहीं है और न्यास के प्रबंधक के विरुद्ध और न्यास के पंजीयन को चुनौती देने वाला वर्तमान वाद विरचित रखने योग्य नहीं है। कहा गया कि मंदिर की स्थापना व्यापक जनता के लाभ के लिए की गई थी और कांकेर शहर की संपूर्ण जनता कांकेर के भूतपूर्व शासक के समय से ही पूजा अर्चना करती आ रही थी। विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि जब मंदिर को स्थायी रूप से बंद पाया गया, तो प्रत्यर्थियों ने, जनता के सदस्यों की सहायता से, मंदिर को खोला और उसका जीर्णोद्धार कराया, क्योंकि मंदिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था। यह विशेष रूप से इंकार कर दिया गया कि वादी संख्या 2 को सर्वाराकार नियुक्त किया गया था। उल्लेख किया गया कि सर्वाराकार की नियुक्ति का अधिकार सरकार का है, क्योंकि मंदिर एक सार्वजनिक न्यास है। संपत्ति के प्रबंधक के रूप में राजस्व अभिलेखों में कलेक्टर, कांकेर का नाम राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांक 12-4-1974 का अनुपालन करते हुए और संपत्ति को जीर्ण-शीर्ण होने से बचाने के लिए अभिलिखित किया गया था। लिखित तर्क में यह भी उल्लेख किया गया था कि वादी संख्या 2 केवल एक पुजारी है और उसे कभी सर्वाराकार नियुक्त नहीं किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अधीनस्थ न्यायालय में, वादीगण ने वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए व्यव्हार प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23-11-1992 को निरस्त कर दिया गया, हालांकि, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कांकेर के न्यायालय ने दिनांक 14-3-1995 के अपने आदेश द्वारा व्यव्हार पुनरीक्षण संख्या 1/92 में पुनरीक्षण स्वीकार करते हुए वादीगण के व्यव्हार प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अधीन आवेदन को स्वीकार कर लिया।

7. विचारण के दौरान, प्रत्यर्थीगण को एकपक्षीय मानकर कार्यवाही अग्रेषित की गई और वादी संख्या 2 लक्ष्मीनारायण का एकपक्षीय साक्ष्य (अ.सा.-1) के रूप में

और उसके गवाहों, यथा, बद्रीनारायण का (अ.सा.-2) के रूप में और कन्हैयालाल का (अ.सा.-3) के रूप में अभिलिखित किया गया।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने, अपने निर्णय और डिक्री दिनांक 31-7-2006 द्वारा, यह अभिनिर्धारित किया कि वादी संख्या 2 लक्ष्मीनारायण वादी संख्या 1, देवता का सर्वाराकार घोषित किए जाने का हकदार नहीं है और वादी प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, कांकेर द्वारा दिनांक 16-8-1994 को सार्वजनिक ट्रस्टों के रजिस्टर में अभिलिखित किए गए सार्वजनिक न्यास की वैधता के संबंध में अतिरिक्त विवाद्यक संख्या 5 का भी वादीगण के विरुद्ध निर्णय लिया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि वादी सार्वजनिक न्यास के पंजीयन के अवैध होने की घोषणा प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। विवाद्यक संख्या 2 पर, अधीनस्थ न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राजस्व अभिलेखों में कलेक्टर, कांकेर के नाम का अभिलिखित किया जाना न तो अवैध है और न ही शून्य होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अधीनस्थ न्यायालय ने, प्रदर्श-पी.-27, प्रदर्श-पी.-28 और प्रदर्श-पी.-29 का उल्लेख करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यद्यपि वादी संख्या 2 के पूर्वज, यथा, सुंदर सिंह, पदम और पन्नालाल सर्वाराकार थे, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि वादी संख्या 2 को कभी भी सर्वाराकार घोषित किया गया था या उसने किसी भी समय सर्वाराकार के रूप में कार्य किया था। अन्य राजस्व अभिलेखों का उल्लेख करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि वादी संख्या 2 ने अपना नाम राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित कराने के प्रयास किए, चूंकि तहसीलदार या नजूल अधिकारी द्वारा विभिन्न समयों पर आक्षेपित आदेशों को अंततः कलेक्टर द्वारा अपास्त कर दिया गया था, वादी संख्या 2 को संपत्ति या मंदिर का स्वामी या सर्वाराकार का दर्जा प्राप्त नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय का यह विशेष निष्कर्ष है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत "विधि माल रियासत, कांकेर" शीर्षक वाले दस्तावेज में उपबंधों/उल्लेखों के आलोक में यह स्थापित होता है कि सर्वाराकार की नियुक्ति का अधिकार कांकेर राज्य में निहित था और सर्वाराकार के पद का अधिकार वंशानुगत नहीं था।

10. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादीगण की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वाद संपत्ति में वादी संख्या 1, देवता का स्वामित्व घोषित किया, हालांकि, यह भी घोषित किया गया कि वादी संख्या 2 मंदिर का सर्वाराकार नहीं है, बल्कि केवल एक पुजारी है और उसे पुजारी के रूप में अपने पारिश्रमिक

पाने का हक होगा। अपीलीय न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि वादी संख्या 1 को यथोचित रूप से सार्वजनिक न्यास घोषित किया गया है और ऐसी न्यास की घोषणा के बाद वादी संख्या 2 को मंदिर का पुजारी घोषित किया गया है, इसलिए, यह घोषणा प्राप्त करने की उसकी याचिका कि वह मंदिर का सर्वाराकार है, स्वीकार योग्य नहीं है।

11. द्वितीय अपील को स्वीकार करते समय, इस न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न विधि का गठन किया था:

> "क्या अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी संख्या 2 न्यास का सर्वाराकार नहीं है, विधि के विपरीत है?"

12. ऊपर गठित महत्वपूर्ण प्रश्न विधि पर विचार करने से पहले, शेवैतिप (वर्तमान मामले में सर्वाराकार के रूप में संदर्भित) की अवधारणा, विधिक चरित्र और घटना का उल्लेख करना लाभप्रद होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ न्यास अधिनियम, टैगोर लॉ लेक्चर्स, बी.के. मुखर्जी द्वारा, पांचवां संस्करण, पुनर्मुद्रण 2003, में अध्याय 5, अर्थात्, मूर्ति की संपत्ति का प्रबंधन—शेवैतिप—इसका विधिक चरित्र और घटनाएं, के कण्डिका 5.1A में, इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है:

> "**5.1A. शेवैत - देवता का प्रबंधन।** —..... "एक आदर्श अर्थ में ही समर्पित संपत्ति एक मूर्ति में निहित होती है," और चीजों की प्रकृति में इसके कब्जे और प्रबंधन को किसी व्यक्ति को शेवैत या प्रबंधन के रूप में सौंपा जाना चाहिए।
>
> "ऐसा प्रतीत होता है," न्यायिक समिति ने ***प्रोसोन्ना कुमारी देब्या बनाम गोलाब चंद बाबू, [(1875) LR 2 IA 145]*** में कहा, "कि जिस व्यक्ति को इतना विश्वास दिया गया है, उसे आवश्यक रूप से देवता की सेवा के लिए और उसकी संपत्ति के लाभ और संरक्षण के लिए आवश्यक कुछ भी करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, कम से कम एक नाबालिग उत्तराधिकारी के प्रबंधक जितना अधिक। यदि ऐसा नहीं होता, तो देवता की संपत्ति नष्ट या बर्बाद हो सकती थी, और उन्हें सुरक्षित रखने और पोषित करने के लिए आवश्यक धनराशि की कमी के कारण उनकी पूजा

बंद हो सकती थी।" देवता के इस मानव सेवक, जो इसका प्रबंधक और विधिक प्रतिनिधि है, को बंगाल और उत्तरी भारत में शेवैत के नाम से जाना जाता है। तमिल और तेलुगु जिलों में उसे धर्मकर्ता कहा जाता है, तंजौर और मालाबार में उरलेन जैसी जगहों पर पंचायतदार कहा जाता है। वह पृथ्वी पर देवता की ओर से बोलने का हकदार व्यक्ति है और उसे इसके सभी सांसारिक मामलों में कार्यवाही का अधिकार प्रदान किया गया है। मंदिर की संपत्ति के संबंध में, प्रबंधक एक ट्रस्टी की स्थिति में है, लेकिन मंदिर की सेवा और उससे जुड़ कर्तव्यों के संबंध में वह प्रतिष्ठा के पद के धारक की स्थिति में है। ***रामनाथन चेट्टी बनाम मुरुगप्पा, [(1906) LR 33 IA 139]*** सुविधा के लिए मैं प्रबंधक को सामान्य नाम शेवैत से पुकारूंगा, हालांकि मैं अवगत हूं कि कुछ मामलों में शेवैत और धर्मकर्ता के बीच अंतर किया गया है।
देखें ***श्रीनिवास बनाम एवलप्पा, [LR 49 IA 237]***\"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लेखक ने आगे कण्डिका 5.1B में पुजारी की स्थिति का वर्णन किया है और पुजारी और शेवैत के बीच अंतर को कण्डिका 5.2 में वर्णित किया गया है। इन दोनों कण्डिकाओ को यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"**5.1B. पुजारी की स्थिति।** — एक पुजारी की नियुक्ति अक्सर संस्थापक या शेवैत द्वारा पूजा का संचालन करने के लिए की जाती है। ***वीरबसवराध्य बनाम लिंगदगुड़ी मठ के भक्त, [AIR 1973 मैसूर 280, 288],*** कण्डिका 20 में एक पुजारी की स्थिति पर विस्तार से विचार किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसी नियुक्ति का पुजारी पर कोई अधिकार प्रदान करने का प्रभाव नहीं होगा। सामान्य तौर पर, वह अपने पद पर पुजारी के रूप में निरंतर बने रहने का हकदार नहीं है। पुजारी या अर्चक किसी भी दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता के लिए हटाए जाने के लिए उत्तरदायी हैं जो उस पद के कर्तव्यों के साथ असंगत होगा जो वे धारण करते हैं।

5.2. पुजारी शेवैत से भिन्न है। — एक पुजारी या अर्चक शेवैत का सेवक है, और उत्तरार्ध के अधिकारों और दायित्वों का कोई भाग उसे हस्तांतरित नहीं किया जाता है। ***आनंद बनाम ब्रोजो, [ILR 50 Cal 292]*** जब किसी पुरोहित की नियुक्ति संस्थापक की इच्छा से हुई है, तो केवल यह तथ्य कि नियुक्त व्यक्तियों ने कई पीढ़ियों तक पूजा की है, नियुक्त परिवार के

सदस्यों पर एक स्वतंत्र अधिकार प्रदान नहीं करेगा और उन्हें पुजारी के रूप में पद पर निरंतर बने रहने के अधिकार का हकदार नहीं बनाएगा। ***कालिकृष्ण बनाम माखनलाल, [ILR 50 Cal 223]*** ।"

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने, ***प्रोफुल्ला चोरोन रक्विट और अन्य बनाम सत्य चोरोन रक्विट, [AIR 1979 SC 1682],*** में कण्डिका 20, 21, 22 और 23 मेंं इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

"20. इन तर्कों के निराकरण से पहले, "शैवायत होने" की अवधारणा, विधिक चरित्र और घटनाओं का स्पष्ट विचार रखना उचित होगा। एक मूर्ति को समर्पित संपत्ति केवल एक आदर्श अर्थ में ही उसमें निहित होती है; आवश्यकता के अनुसार, कब्जे और प्रबंधन को किसी मानव अभिकर्ता को सौंपा जाना चाहिए। ऐसे मूर्ति के अभिकर्ता को उत्तरी भारत में शेवैत के रूप में जाना जाता है। एक शेवैत के विधिक चरित्र को सटीकता और शुद्धता के साथ परिभाषित नहीं किया जा सकता है। मोटे तौर पर वर्णित वह मूर्ति का मानव सेवक और संरक्षक है, इसका सांसारिक प्रवक्ता, इसका अधिकृत प्रतिनिधि जो इसके सभी सांसारिक मामलों में कार्यवाही और इसकी संपत्ति के प्रबंधन का हकदार है। मूर्ति की संपत्ति के प्रशासन के संबंध में, उसकी स्थिति एक ट्रस्टी के अनुरूप है; फिर भी, वह अंग्रेजी अर्थ में एक ट्रस्टी की स्थिति में ठीक से नहीं है, क्योंकि हिंदू विधि के द्वारा, एक मूर्ति को पूर्ण रूप से समर्पित संपत्ति, मूर्ति में निहित होती है, न कि शेवैत में। हालांकि मूर्ति की संपत्ति कभी भी शेवैत में निहित नहीं होता है, फिर भी, विचित्र रूप से, लगभग हर मामले में, शेवैत को उपयोग के एक हिस्से का अधिकार होता है, आनंद लेने का तरीका, और उपयोग की राशि फिर से उपयोग और प्रथा पर निर्भर करती है, यदि संस्थापक द्वारा निर्दिष्ट नहीं की गई है।

21. मंदिर की सेवा और उससे जुड़े कर्तव्यों के संबंध में, वह एक पद के धारक की स्थिति में है; लेकिन फिर भी, शेवैतिप का वर्णन केवल एक पद के रूप में करना पूर्ण रूप से सही नहीं होगा। "पद और संपत्ति दोनों शेवैतिप की अवधारणा में सम्मिलित हैं"। धर्मादा से जुड़े उस पर टिके दायित्वों और कर्तव्यों के अलावा, शेवैत का समर्पित संपत्ति में एक व्यक्तिगत हित होता है। उसके पास एक सीमित मालिक के रूप में कुछ सीमा तक ही अधिकार प्राप्त हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. शेवैतिप संपत्ति होने के नाते, यह किसी अन्य प्रकार की वंशानुगत संपत्ति की तरह हस्तांतरित होती है। इसका तात्पर्य यह है कि, जहां संस्थापक उसके द्वारा सृजित धर्मादा में शेवैती अधिकारों का निराकृत नहीं करता है, तो शेवैतिप हिंदू विधि के अनुसार संस्थापक के उत्तराधिकारियों पर हस्तांतरित हो जाती है, यदि कोई भिन्न प्रकृति का उपयोग या प्रथा विद्यमान नहीं दिखाई जाती है। **(गोसामी श्री ग्रीधारीजी बनाम रुमनलोलजी, पूर्वोक्त)**।

23. फिर, एक सार्वजनिक और व्यक्तिगत मूर्ति की संपत्ति के बीच अंतर है। एक सार्वजनिक मूर्ति की संपत्ति या धर्मादा में, समर्पण जनता के उपयोग या लाभ के लिए होता है। लेकिन एक व्यक्तिगत धर्मादा में, जब संपत्ति किसी पारिवारिक मूर्ति की पूजा के लिए अलग रखी जाती है, तो जनता की कोई रुचि नहीं होती है। वर्तमान प्रकरण एक व्यक्तिगत मूर्ति की संपत्ति का है। अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे तार्किक रूप से परिणामी परिणामों को न्यायालयों द्वारा अलग-अलग तरीके से लागू किया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. जब शेवैत के पद की प्रकृति, इसकी अवधारणा और इसके विधिक चरित्र के रूप में विधि इस प्रकार खड़ा है, तो यह न्यायालय अब यह विवेचना करेगा कि क्या अधीनस्थ न्यायालय के ये निष्कर्ष कि अपीलार्थी संख्या 2 न्यास का सर्वाराकार नहीं है, विधि के विपरीत हैं (जैसा कि गठित महत्वपूर्ण प्रश्न विधि में उल्लेखित है, हालांकि, यह मंदिर का सर्वाराकार होना चाहिए था, न्यास का नहीं)।

15. अपीलार्थियों के विद्वान् अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर अवलेख किया है कि सर्वाराकार का पद संपत्ति की प्रकृति में होने के कारण वंशानुगत है, इसलिए, वादी संख्या 2 पूर्ववर्ती सर्वाराकार का उत्तराधिकारी और वैध उत्तराधिकारी होने और वह मंदिर का प्रभारी होने के नाते, अधीनस्थ न्यायालय ने एक गलत और विधि के विपरीत निष्कर्ष अभिलेख किया है कि वादी संख्या 2 न्यास/मंदिर का सर्वाराकार नहीं है। निर्णय हैं: ***शंभू चरण शुक्ला बनाम श्री ठाकुर लाडली राधा चंद्र मदन गोपालजी महाराज और एक अन्य, [AIR 1985 SC 905], श्रीमती रालकिशोरी दासी बनाम ऑफिसियल ट्रस्टी ऑफ वेस्ट बंगाल और अन्य, [AIR 1960 Cal 235], जानकी रमन पी. मिश्रा और एक अन्य बनाम कोशलयानंदन पी. मिश्रा और अन्य, [AIR 1961 Pat***

293], कचा कांति सेवा समिति और एक अन्य बनाम कचा कांति देवी और अन्य, [AIR 2004 SC 608], रामानुजाचार्युलु और एक अन्य बनाम पांडुरंगाचार्युलु और अन्य, [AIR 1957 AP 272] और नारायणम शेषाचार्युलु और एक अन्य बनाम नारायणम वेंकटाचार्युलु, [AIR 1957 AP 876] ।

16. आगे बढ़ने से पहले, वाद के गठन में दोषों का उल्लेख करना अनिर्णीत विषय है, हालांकि इन दोषों के संबंध में कोई विवाद्यक प्रश्न नहीं बनाया गया था। वादपत्र में यह घोषणा मांगी गई है कि सार्वजनिक न्यास का पंजीयन शून्य घोषित किया जाए फिर भी न तो न्यास और न ही न्यासियों को वाद में पक्ष-प्रत्यर्थी के रूप में शामिल किया गया है। ऐसी अनुतोष केवल छत्तीसगढ़ सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के द्वारा प्रदान की गई शैली में ही दावा की जा सकती है, जिसमें धारा 8 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक ट्रस्टों के रजिस्टर में किए गए प्रविष्टियों, न्यास और संपत्ति के संबंध में पंजीयक, सार्वजनिक न्यास द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों को चुनौती देने वाला वाद व्यव्हार न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है अर्थात मूल अधिकारिता का प्रधान व्यव्हार न्यायालय, यानी जिला न्यायाधीश का न्यायालय। वर्तमान वाद व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। यह घोषणा मांगकर कि न्यास का पंजीयन शून्य है, वादी अपने कथित/स्व-दावाकृत सर्वाराकार, यानी वादी संख्या 2 के माध्यम से संकेतित रूप से यह घोषणा मांगते हैं कि मंदिर एक व्यक्तिगत मंदिर है और इसके संस्थापक ने देवता की प्रतिष्ठा और स्थापना करने तथा ग्राम बांसपत्तर में स्थित कृषि भूमि को देवता को दान/उपहार में देकर वादी संख्या 2 के पूर्वजों को सर्वाराकार नियुक्त किया था। वादपत्र में कहा गया है कि कांकेर राज्य के भूतपूर्व शासक ने संपत्ति दान/उपहार में दी थी और वर्तमान महाराजाधिराज श्री उदय प्रताप देव ने 1985 में मंदिर को आम जनता के लिए खोल दिया था। इस प्रकार तर्क देकर और संकेतित रूप से दावा करके कि मंदिर एक व्यक्तिगत मंदिर है हालांकि केवल पूजा के उद्देश्य से जनता के लिए खोला गया, वादीगण ने कांकेर राज्य के भूतपूर्व शाही परिवार के किसी भी सदस्य को, जो मंदिर के संस्थापक हैं, शामिल नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. व्यव्हार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के द्वारा दिनांक 21-1-1992 की सूचना (प्रदर्श-पी -1) तथा वाद पत्र में, वादी संख्या 2 ने दावा किया है कि वह मंदिर का सर्वाराकार(प्रबंधक) के साथ-साथ पुजारी भी है। वह यह भी कहता है कि मंदिर के उपासकों और अनुयायियों ने उसे सर्वाराकार नियुक्त किया है (वाद पत्र

का कण्डिका 7 और व्यव्हार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के द्वारा दी गई सूचना का कण्डिका 6)। इस प्रकार, सर्वाराकार के पद पर उसके दावे की विवेचना संस्थापक द्वारा मूर्ति को सम्पत्ति के दान, इसमें सर्वाराकार की नियुक्ति के लिए किए गए प्रावधान और बाद में सार्वजनिक न्यास(न्यास) के पंजीकरण, जिसे इस वाद में अपास्त करने का प्रयास किया गया है, को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। प्रदर्श-पी-27 वर्ष 1944 का एक दस्तावेज है जिसका शीर्षक "ग्राम बांसपत्तर में स्थित भूमि का पट्टा" है। इस दस्तावेज में सुंदर सिंह का नाम वादी संख्या 1 के सर्वाराकार के रूप में उल्लेखित है। इसी प्रकार, प्रदर्श-पी - 28 ग्राम बांसपत्तर की भूमि के संबंध में कांकेर राज्य के शासक प्रमुख और कांकेर राज्य के दीवान के हस्ताक्षरों से जारी एक पट्टा माफ़ीदारी है, जिसमें उल्लेख है कि ग्राम बांसपत्तर की भूमि मंदिर की पूजा और रख-रखाव के लिए वादी संख्या 1 को प्रदान की गई है। इस प्रकार भूमि मूर्ति के नाम पर माफ़ी-भूमि थी। निर्णय के कण्डिका 17 में, अधीनस्थ न्यायालय ने विधि माल रियासत कांकेर, 1909 में निहित प्रावधानों का उल्लेख किया है और उक्त कण्डिका में इसकी धारा 132, 133 और 223 को उद्धृत किया है, जिसे यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 17. विधि माल रियासत कांकेर 1909 ई० की दफ़ा 4 के अनुसार लफ्ज गोटिया से गांव का ठेकेदार, शिकमी ठेकेदार, और माफीदार मुराद है।" दफा 132 के अनुसार " माफीदार उसे कहते है जिसे या जिसके खानदान में किसी शक्स को सरकार स्टेट की तरफ से गांव या जमीन माफी में मिली हो, और जिस पर यह शक्स माफी में काबिज हो ।
>
> दफा-133. रियासत हाजा में माफीदार चार प्रकार के हैं :-
>
> (1) माफीदार ता आल औलाद, जिनसे माफी मौजा (गांव) की आमदनी से कुछ भी रकम माफीदार को सरकार स्टेट के खजाना में दाखल करना नहीं होती.
>
> (2) माफीदार जिन्हें ता आल औलाद, मांफी गांव में है, मगर उन्हें जो अब्बाब (सेसज) की रक जो वक्त बंदोबस्त के मुकर्रर होती है दाखल खजाना करना पड़ता है.
>
> (3) माफीदार जिन्हें ताहयात माफी में गांव मिला हो, वो उन्हें अब्बाब की रकम जो वक्त बन्दोबस्त में मुकर्रर की जाती है. दाखल खजाना करना पड़ता है,
>
> (4) रेजा माफीदार जिन्हें सिर्फ जमीन कास्तकारी की ताहयात

माफी मिली है.

(1) देवताओं में जो माफी मौजा दिया गया है. वह नम्बर 3 में शुमार है।

दफा-223. कोई गौटिया नाबालिग या औरत या पागल या कम अक्ल वाला या जईफ (बुढा) या किसी बीमारी के कारण किसी सबब से बदन की कमजोरी हो तो वह अपने वलिजायज या आप खुद किसी लायक शक्स को अपने गांव या खेती के कारवार चलाने के वास्ते सरबराहकार ब मंजूरी सरकार के स्अअ केमुकर्रर कर सकता है।

नीचे लिखी हुई पांच सूरतों में आये हुए शक्स सरबराहकार मुकर्रर नहीं हो सकता,

(1) जो औरत हो,
(2) जिसकी चाल चलन अच्छी न हो.
(3) जिसकी उमर 18 साल से कम और 50 साल से ज्यादह हो,
(4) जो पागल और कम अक्ल हो,
(5) जो बदन से कमजोर हो."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. उपर उद्धृत विधि माल रियासत कांकेर, 1909 की धारा 132, 133 और 223 के संयुक्त अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि माफी-जमीनों के संबंध में माफीदार या गोंटिया, कांकेर राज्य की पूर्व स्वीकृति से सर्वाराकार नियुक्त कर सकते थे। इस प्रकार, सर्वाराकार की नियुक्ति केवल कांकेर राज्य की पूर्व स्वीकृति से ही की जा सकती थी। वादी संख्या 2 के पूर्वज को सर्वाराकार की नियुक्ति 1944 में की गई थी, हालांकि, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि किसी भी समय वादी संख्या 2 को कांकेर राज्य के शासक या उनके वर्तमान उत्तराधिकारियों, यानी राजपरिवार के सदस्यों (जिनके नाम वाद पत्र में उल्लेखित हैं) द्वारा नियुक्त किया गया था। इसलिए, वर्तमान प्रतीकात्मक शासक, यानी कांकेर के महाराजाधिराज को पक्षकार न बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि, वादी संख्या 2 ने यह तर्क नहीं दिया है कि उसे वर्तमान महाराजाधिराज द्वारा सर्वाराकार नियुक्त किया गया था, जिनके पूर्वजों/बुजुर्गों ने संपत्ति मूर्ति को समर्पित की थी। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि विधि माल रियासत कांकेर के द्वारा, जिसके अंतर्गत संपत्ति मंदिर को माफी-जमीन के रूप में समर्पित की गई थी, यह

प्रावधान नहीं था कि सर्वाराकार का पद उत्तराधिकार से होता है, बल्कि इसकी नियुक्ति केवल कांकेर राज्य की पूर्व स्वीकृति से ही की जा सकती थी और वर्तमान मामले में वादी संख्या 1 (मंदिर) का सर्वाराकार का पद वंशानुगत नहीं था।

19. उपरोक्त के अलावा, वादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि उसने प्रदर्श.पी.-12 के माध्यम से पंजीयक, सार्वजनिक न्यास के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत की थीं जब सार्वजनिक न्यास के पंजीयन की कार्यवाही शुरू की गई थी। पंजीयक ने, आदेश दिनांक 16-8-1994 (प्रदर्श.पी.-13) द्वारा, मंदिर को सार्वजनिक न्यास घोषित किया और इसके पंजीयन का आदेश दिया। उक्त आदेश में, श्री उदय प्रताप देव, महाराजाधिराज का नाम एक ट्रस्टी के रूप में उल्लेखित किया गया है। वादी संख्या 2 का स्वयं का नाम भी उक्त आदेश में एक ट्रस्टी के रूप में उल्लेखित किया गया है। वाद भूमि को अन्य संपत्ति के साथ न्यास की संपत्ति घोषित किया गया। श्री तिलक कुमार दुबे को पंजीयक, सार्वजनिक न्यास द्वारा प्रबंधकीय ट्रस्टी नामित किया गया... वादी संख्या 2 द्वारा नजूल अधिकारी, कांकेर के समक्ष मंदिर संपत्ति में उसके नाम को सर्वाराकार के रूप में अभिलिखित कराने के लिए प्रस्तुत आवेदन दिनांक 8-11-2002 (प्रदर्श.पी.-15) को स्वीकार कर लिया गया। उक्त आदेश को कलेक्टर, कांकेर द्वारा दिनांक 11-11-2004 को प्रदर्श.पी.-18 के माध्यम से अपास्त कर दिया गया और कलेक्टर, कांकेर का नाम संपत्ति के प्रबंधक के रूप में पुनः अभिलिखित किया गया। प्रदर्श.पी.-19 से, जो नायब--तहसीलदार, नरनारपुर, जिला कांकेर द्वारा दिनांक 12-1-2001 को आक्षेपित एक आदेश है, यह प्रतीत होता है कि एक केशरबाई सुंदर सिंह की बेटी थी, उसकी बहन सोनबती थी। उक्त केशरबाई ने लक्ष्मीनारायण के पक्ष में एक वसीयतनामा निष्पादित किया क्योंकि केशरबाई की कोई संतान नहीं थी। स्पष्ट रूप से, सुंदर सिंह का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, इस प्रकार, अन्यथा भी, लक्ष्मीनारायण सुंदर सिंह से संबंधित नहीं था, इसलिए, वादी संख्या 2 का उत्तराधिकार द्वारा सर्वाराकार के अधिकार के अधिग्रहण का तर्क चलने योग्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. निर्विवाद रूप से, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के द्वारा एक सार्वजनिक न्यास पहले ही पंजीकृत हो चुका है और देवता द्वारा धारित संपत्ति को पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, कांकेर द्वारा रखे गए सार्वजनिक ट्रस्टों के रजिस्टर में न्यास के नाम पर अभिलिखित किया जा चुका है। एक प्रबंधकीय ट्रस्टी पहले ही पंजीयक, सार्वजनिक न्यास द्वारा नियुक्त किया जा चुका है,

इसलिए, जब तक उक्त सार्वजनिक न्यास का पंजीयन अपास्त नहीं किया जाता है, वादी संख्या 2 यह घोषणा प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता कि उसे मंदिर का सर्वाराकार घोषित किया जाए। चूंकि सर्वाराकार एक व्यक्तिगत मंदिर के मामले में मंदिर के प्रबंधक या ट्रस्टी की प्रकृति में है, वादी संख्या 2 द्वारा मांगी गई अनुतोष वर्तमान वाद में प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि सार्वजनिक न्यास के पंजीयन को शून्य घोषित करने की उसकी मांग पहले ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है और इस न्यायालय ने निर्णय और डिक्री के उस हिस्से की वैधता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न विधि का गठन नहीं किया है। अन्यथा भी, ऐसी अनुतोष एक ऐसे वाद में प्रदान नहीं की जा सकती जहां सार्वजनिक न्यास और न्यासियों को व्यव्हार प्रक्रिया संहिता के आदेश 31 के नियम 2 में निहित प्रावधानों के अनुसार पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया हो। न्यासियों को शामिल करना और भी आवश्यक था जब वादी संख्या 2 ने वाद प्रस्तुत करने की अनुमति मांगने के लिए व्यव्हार प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के द्वारा एक आवेदन दिया था और उक्त याचिका स्वीकार कर ली गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. वादीगण/अपीलार्थियों द्वारा अवलेख किए गए निर्णय/वाद न्यायालय इस प्रभाव के हैं कि सर्वाराकार का पद वंशानुगत है। निर्णय वर्तमान मामले की तथ्यात्मक परिस्थितियों में भिन्न हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने **प्रोफुल्ला चोरोन रक्विट और अन्य बनाम सत्य चोरोन रक्विट (पूर्वोक्त)** में रिपोर्ट के कण्डिका 22 में अभिनिर्धारित किया है कि "शेवैतिप संपत्ति होने के नाते, यह किसी अन्य प्रकार की वंशानुगत संपत्ति की तरह हस्तांतरित होती है, इसका तात्पर्य यह है कि, जहां संस्थापक उसके द्वारा सृजित धर्मादा में शेवैती अधिकारों का निराकृत नहीं करता है, तो शेवैतिप हिंदू विधि के अनुसार संस्थापक के उत्तराधिकारियों पर हस्तांतरित हो जाती है, यदि कोई भिन्न प्रकृति का उपयोग या प्रथा विद्यमान नहीं दिखाई जाती है"। वर्तमान मामले में, एकमात्र निराकृत किये जाने उपलब्ध विधि माल रियासत कांकेर, 1909 है जिसके द्वारा मंदिर को संपत्ति माफी-भूमि के रूप में दान में दी गई थी, जिसमें एक खंड था कि सर्वाराकार की नियुक्ति गोंटिया द्वारा कांकेर राज्य की पूर्व स्वीकृति के साथ की जाएगी। इस प्रकार, अपीलार्थियों द्वारा अवलेख किए गए निर्णय वर्तमान मामले की तथ्यात्मक परिस्थितियों में लागू नहीं हैं।

22. ***मूर्ति गणेशजी महाराज और अन्य बनाम जे.एम. आनंद और एक अन्य, [1983 JLJ 248***] में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक विद्वत एकल न्यायाधीश ने एक शेवैत के पद और अधिकारों की प्रकृति से संबंधित विधि से निपटा है। चूंकि

मैंने **प्रोफुल्ला चोरोन रक्विट और अन्य बनाम सत्य चोरोन रक्विट (पूर्वोक्त)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि का पहले ही उल्लेख कर दिया है, मुझे **मूर्ति गणेशजी महाराज और अन्य बनाम जे.एम. आनंद और एक अन्य** में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वादी संख्या 2 ने व्यव्हार प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के द्वारा एक आवेदन दिया था। एक सार्वजनिक न्यास और एक व्यक्तिगत न्यास के बीच अंतर और एक सार्वजनिक न्यास के संबंध में व्यव्हार प्रक्रिया संहिता की धारा 92 का अनुप्रयोग और कैसे यह एक व्यक्तिगत न्यास या एक व्यक्तिगत मूर्ति की संपत्ति के मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं रखता है, इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***महंत राम स्वरूप दासजी बनाम एस.पी. साही, हिंदू धार्मिक ट्रस्टों के प्रभारी विशेष अधिकारी और अन्य, [AIR 1959 SC 951]*** में विचार किया है। *यह निर्णय उन धर्मार्थ न्यासों के बीच मूलभूत अंतर पर भी विचार करता है जो सार्वजनिक हैं और व्यक्तिगत हैं। कंडिका 6, 7, 9 और 10 से निर्णय के प्रासंगिक अंश इस प्रकार पढ़े जाते हैं:*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **"6.** ..... इस तर्क को समझने के लिए सबसे पहले हिंदू कानून में सार्वजनिक और व्यक्तिगत धार्मिक अंबद्धताओं (धार्मिक न्यासों) के बीच के अंतर को बताना आवश्यक है। संक्षेप में कहें तो मूल अंतर यह है कि एक सार्वजनिक न्यास में लाभकारी हित अनिश्चित और परिवर्तनशील व्यक्तियों के समूह में निहित होता है, जो या तो समस्त जनता होती है या कोई विशेष विवरण को पूरा करने वाली उसकी एक बड़ी भागीदारी होती है; जबकि एक व्यक्तिगत न्यास में लाभार्थी निश्चित और पहचाने गए व्यक्ति होते हैं या वे लोग होते हैं जिन्हें एक निश्चित समय के भीतर निश्चित रूप से पहचाना जा सकता है। यह तथ्य कि अनिश्चित और परिवर्तनशील व्यक्तियों का समूह किसी विशेष धार्मिक मत का पालन करने वाली जनता का एक हिस्सा है या केवल एक निश्चित धार्मिक विश्वास वाले लोगों का एक संप्रदाय है, इस मामले में कोई अंतर नहीं लाएगा और न्यास को एक व्यक्तिगत न्यास नहीं बनाएगा। .....
>
> **7**. ..... 1877 की व्यवहार प्रक्रिया संहिता में एक विशिष्ट धारा, अर्थात धारा 539, शामिल की गई थी, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए स्थापित किसी भी स्पष्ट या निहित न्यास के कथित उल्लंघन की स्थिति में एक वाद प्रस्तुत किया जा सकता था। इस धारा में बाद में संशोधन किया गया, और इसी संशोधित रूप में यह

वर्तमान व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 92 बन गई, जिसके दायरे में कोई मामला लाने के लिए आवश्यक पहली शर्त एक न्यास का अस्तित्व है, चाहे वह धार्मिक या चैरिटेबल प्रकृति के 'सार्वजनिक उद्देश्यों' के लिए स्पष्ट या निहित हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक व्यक्तिगत न्यास व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के प्रभावक्षेत्र से बाहर है। .....

9. ..... हिंदू विधि में सार्वजनिक और व्यक्तिगत धर्मादाओं के बीच अंतर पर विचार करते हुए, सर दिनशा मुल्ला ने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ (11वां संस्करण) के पृष्ठ 529 पर कहा है—

"धार्मिक धर्मादाएं या तो सार्वजनिक या व्यक्तिगत होती हैं। एक सार्वजनिक धर्मादा में समर्पण जनता के उपयोग या लाभ के लिए होता है। जब संपत्ति किसी पारिवारिक देवता की पूजा के लिए अलग रखी जाती है जिसमें जनता की कोई रुचि नहीं होती है, तो धर्मादा एक व्यक्तिगत होती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्ट रूप से, परिभाषा खंड केवल ऊपर वर्णित एक व्यक्तिगत अंतःपुर का विशिष्ट उदाहरण उद्धृत करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि कुलदेवता की पूजा के लिए बनाए गए अंतःपुर का अपवर्जन उसके बाद आने वाले विशेषणिक उपवाक्य पर आधारित है, अर्थात "जिसमें जनता की रुचि नहीं है"। दूसरे शब्दों में, यह अपवर्जन हिंदू कानून में एक सार्वजनिक और व्यक्तिगत न्यास के बीच मौलिक अंतर पर आधारित है। यदि कसौटी यह है कि जनता या उसके किसी वर्ग की न्यास में कोई रुचि नहीं है, तो ऐसी कसौटी हिंदू कानून में 'सभी' व्यक्तिगत न्यासों की विशेषता है। उक्त तथ्य यह भी दर्शाता है कि ऐसा भी न्यास हो सकता है जो किसी कुलदेवता की पूजा के लिए बनाया गया हो लेकिन जिसमें जनता की रुचि हो। ये ऐसे न्यासों के मामले हैं जो एक व्यक्तिगत न्यास के रूप में शुरू हुए लेकिन अंततः जनता के लिए खोल दिए गए। यह इस बात का भी संकेत देता है कि परिभाषा का उद्देश्य केवल सार्वजनिक न्यासों को शामिल करना था।

10. ..... अब, यह धारा कहती है कि बोर्ड अपनी स्वयं की शक्ति का प्रयोग कर सकता है या किसी न्यास में हितबद्ध दो या अधिक व्यक्तियों

द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर। इस धारा की भाषा, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के बहुत करीब से मेल खाती है, जहाँ तक वाक्यांश "किसी न्यास में हितबद्ध दो या अधिक व्यक्तियों" का संबंध है। यह समझना मुश्किल है कि एक व्यक्तिगत न्यास के मामले में, ऐसे न्यास के लिए एक योजना निराकरण हेतु आवेदन करने के लिए न्यास में हितबद्ध दो या अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक क्यों होना चाहिए। एक व्यक्तिगत या पारिवारिक देवोत्तर में लाभार्थी व्यक्तियों का एक सीमित और निश्चित वर्ग होता है, उदाहरण के लिए, एक परिवार के सदस्य। यदि ट्रस्टी या शेबैत कुप्रबंधन, अपव्यय, देवोत्तर संपत्ति के अवैध अंतरण या कर्तव्यों के अन्य उल्लंघन का दोषी है, तो निश्चित रूप से न्यास के इन दुरुपयोगों के निवारण के लिए एक मुकदमा प्रस्तुत किया जा सकता है। देश के सामान्य कानून के तहत, धर्मस्व की स्थापना करने वाला व्यक्ति (संस्थापक), या उसके किसी भी उत्तराधिकारी को देवोत्तर के उचित प्रशासन, पुराने ट्रस्टी को हटाने और एक नए की नियुक्ति के लिए मुकदमा प्रस्तुत करने का अधिकार है। ऐसे मामले में यह आवश्यक नहीं है कि मुकदमा प्रस्तुत करने के लिए न्यास में हितबद्ध दो या अधिक व्यक्तियों को इसमें शामिल होना चाहिए। "दो या अधिक व्यक्तियों" की शर्त केवल एक सार्वजनिक न्यास के लिए उपयुक्त है, कारण यह है कि एक सार्वजनिक न्यास सार्वजनिक चिंता का विषय होता है। .....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. वादी संख्या 2 द्वारा व्यव्हार प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के द्वारा आवेदन दिया जाना एक सार्वजनिक न्यास के अस्तित्व की पूर्वधारणा के अनुसार है, हालांकि, वादी संख्या 2 ने वाद में न्यास या न्यासियों को पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया है। इसके अलावा, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास द्वारा आक्षेपित आदेश में, एक प्रबंधकीय ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। व्यव्हार प्रक्रिया संहिता की धारा 92 स्वयं न्यास और न्यास संपत्ति के प्रबंधन के लिए मुकदमे का अधीनस्थ करने में सक्षम बनाती है, हालांकि, वादी संख्या 2 ने ऐसी कोई अनुतोष नहीं मांगी है बल्कि उसने अपने स्वयं के लिए अनुतोष मांगी है यह घोषणा मांगकर कि वादी संख्या 2 सर्वाराकार है, जिसका अर्थ है कि उसके पास धर्मादा/मूर्ति की सम्पत्ति से संबंधित संपत्ति में सीमित शेवैती अधिकार हैं। सार्वजनिक न्यास के अस्तित्व के दृष्टिकोण में, वादी संख्या 2 द्वारा मांगी गई घोषणा की ऐसी अनुतोष को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यथोचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है।

24. वादीगण/अपीलार्थियों के विरुद्ध जो कुछ चर्चा और निष्कर्ष निकाला गया है, उससे यह न्यायालय इस राय में है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष कि वादी संख्या 2 वादी संख्या 1/मंदिर के सर्वाराकार के रूप में अपनी नियुक्ति या निरंतरता की घोषणा प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

25. महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया जाता है। वर्तमान द्वितीय अपील, इस प्रकार, विफल होती है और इसे निरस्त किया जाता है।

26. वाद व्यय पर कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

27. तदनुसार एक डिक्री तैयार की जाए।

सही/-
पी.के. मिश्रा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By : ANKIT SHRIVAS